International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
e-ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 01(I), January - March, 2026, pp. 63-70

मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति व चुनौतियाँ का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. देवेंद्र सिंह परमार*

माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला मुंडलकला, सीहोर, मध्यप्रदेश।

*Corresponding Author: lakhanchouksey@gmail.com

Citation: परमार, देवेंद्र (2026). मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति व चुनौतियाँ का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(01(I)), 63–70.

सार

प्रस्तुत शोधपत्र में मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वर्तमान स्थिति, उनके आर्थिक योगदान तथा सामने आ रही प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र राज्य की औद्योगिक संरचना का आधार है और समग्र आर्थिक विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह क्षेत्र राज्य में बड़े पैमाने पर स्व–रोजगार एवं अन्य रोजगार के अवसर सृजित करता है, जिससे आजीविका के वैकल्पिक साधन विकसित होते हैं और सामाजिकदृआर्थिक स्थिरता को बल मिलता है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयाँ स्थानीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायता मिलती है। कम पूंजी निवेश में अधिक उत्पादन एवं रोजगार की क्षमता के कारण इस क्षेत्र का श्रमदृपूंजी अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है, जो इसे समावेशी विकास का प्रभावी माध्यम बनाता है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई विनिर्माण, सेवा तथा सहायक उद्योगों के विकास में सहायक होकर राज्य की आर्थिक विविधता को सुदृढ़ करते हैं। हालाँकि, वित्त की उपलब्धता, उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव, कौशल विकास की कमी, विपणन संबंधी कठिनाइयाँ तथा अवसंरचनात्मक समस्याएँ एमएसएमई के सतत विकास में प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु प्रभावी नीतिगत समर्थन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा नवाचार को प्रोत्साहन आवश्यक है, जिससे मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को दीर्घकालिक और संतुलित विकास की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

शब्दकोशः *सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय संतुलन, वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन, औद्योगिक नीति मध्य प्रदेश।*

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र राज्य की औद्योगिक संरचना का आधार स्तंभ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय योगदान देने के साथ–साथ व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन, आय वितरण में संतुलन तथा स्थानीय संसाधनों के उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करता है। भौगोलिक दृष्टि से

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

विशाल और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र औद्योगिक विकेंद्रीकरण तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास का प्रभावी साधन बनकर उभरा है।

राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयाँ वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, वन–आधारित उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, हस्तशिल्प तथा कृषि–आधारित उद्योगों जैसे विविध क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। इन उद्योगों ने न केवल पारंपरिक कौशल और स्थानीय कच्चे माल को बाजार से जोड़ा है, बल्कि ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं लघु उद्यमिता को भी प्रोत्साहित किया है। राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम, निवेश संवर्धन योजनाएँ तथा सिंगल–विंडो प्रणाली जैसी पहलों ने इस क्षेत्र को संस्थागत आधार प्रदान किया है।

इसके बावजूद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र अनेक संरचनात्मक और परिचालनगत चुनौतियों से जूझ रहा है। क्षेत्रीय असंतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित हैं। अवसंरचनात्मक कमियाँ जैसे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, परिवहन सुविधा और औद्योगिक क्लस्टरों का अभाव उत्पादन लागत को प्रभावित करती हैं। वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में जटिल प्रक्रियाएँ तथा जमानत संबंधी शर्तें सूक्ष्म इकाइयों के लिए बाधक सिद्ध होती हैं। साथ ही, तकनीकी आधुनिकीकरण की कमी, डिजिटल विपणन के सीमित उपयोग और गुणवत्ता मानकों के पालन में कठिनाइयाँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कम करती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इकाइयाँ विशेष रूप से पूंजी, प्रशिक्षित मानव संसाधन और बाज़ार सूचना के अभाव से प्रभावित हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान तथा निर्यात–उन्मुख मानकों की अनिवार्यता ने चुनौतियों को और जटिल बनाया है। अतः मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, इसकी संभावनाओं और समस्याओं की समग्र समझ के लिए अत्यंत आवश्यक है।

Singh, A. K. and Shrivastav, P. K. (2022) प्रस्तुत शोध पत्र में शोधकर्ताओं ने लघु उद्योगों की वर्तमान चुनौतियों एवं भावी संभावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अध्ययन का मूल उद्देश्य भारत के समग्र आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका का आकलन करना, उनकी प्रमुख समस्याओं की पहचान करना तथा उनके प्रदर्शन और अवसरों का मूल्यांकन करते हुए व्यावहारिक समाधान सुझाना है। विशेष रूप से यह शोध इस बात पर केंद्रित है कि लघु उद्योग किस प्रकार रोजगार सृजन, आय वितरण में संतुलन तथा क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करते हैं, और किन संरचनात्मक बाधाओं के कारण उनकी विकास क्षमता पूर्णतः साकार नहीं हो पा रही है।

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों का संकलन व्यक्तिगत साक्षात्कार, संरचित प्रश्नावली तथा प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से किया गया, जिससे वास्तविक परिस्थितियों का तथ्यात्मक आकलन संभव हो सका। द्वितीयक समंकों के अंतर्गत विभिन्न प्रकाशित सरकारी रिपोर्टें, शोध लेख, समाचार पत्र, आधिकारिक आँकड़े तथा इंटरनेट स्रोतों का उपयोग किया गया। संकलित समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर परिकल्पनाओं की जाँच हेतु काई–वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया, जिससे निष्कर्षों की वैधता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि लघु उद्योग भारत के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग अपेक्षाकृत कम पूंजी में अधिक रोजगार सृजित करते हैं तथा ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में आय के स्रोत उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, ये स्थानीय संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान देते हैं।

हालाँकि, लघु उद्योग अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें वित्तीय संसाधनों की कमी, संस्थागत ऋण तक सीमित पहुँच, कुशल श्रमिकों का अभाव, कच्चे माल की उच्च लागत एवं गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ प्रमुख हैं। प्रबंधकीय दक्षता की कमी तथा तकनीकी आधुनिकीकरण का अभाव भी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रभावित करते हैं।

शोधकर्ताओं का मत है कि यदि इन समस्याओं का योजनाबद्ध समाधान किया जाए, वित्तीय सहायता सुलभ बनाई जाए, कौशल विकास हेतु नवीन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए तथा प्रबंधकीय क्षमता को सुदृढ़ किया जाए, तो लघु उद्योगों का सतत विकास संभव है। इससे न केवल उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि भारत की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

Shashank, B. S. and Mayya, S. (2021) प्रस्तुत शोध पत्र में शोधकर्ताओं ने भारत में लघु उद्योगों के प्रदर्शन, निवेश प्रवृत्तियों तथा उपलब्ध अवसरों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन एवं निवेश के अवसरों में संभावित वृद्धि का मूल्यांकन करना, लघु उद्योगों के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा उनके सतत् विकास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है। यह शोध इस तथ्य पर आधारित है कि लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और कम पूंजी में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं।

यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक समंकों पर आधारित है। आवश्यक आँकड़ों का संकलन विभिन्न प्रकाशित रिपोर्टों, शोध पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं तथा सरकारी एजेंसियों की आधिकारिक वेबसाइटों से किया गया है। इन स्रोतों से प्राप्त तथ्यों एवं आँकड़ों का व्यवस्थित वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर तार्किक निष्कर्ष निकाले गए हैं। द्वितीयक समंकों के तुलनात्मक एवं प्रवृत्तिगत विश्लेषण के माध्यम से लघु उद्योगों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया गया है।

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि लघु उद्योग भारत में व्यापक संभावनाओं के बावजूद अनेक संरचनात्मक एवं प्रबंधकीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता, ऋण की उच्च लागत, कार्यशील पूंजी की कमी तथा संस्थागत वित्त तक सीमित पहुँच प्रमुख समस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबंधकीय कौशल का अभाव, विपणन रणनीतियों की कमजोरी तथा नवीन तकनीकों को आत्मसात करने में असमर्थता भी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रभावित करती है। तकनीकी उन्नयन में विलंब के कारण उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

शोधकर्ताओं का मत है कि इन चुनौतियों का योजनाबद्ध समाधान कर लघु उद्योगों के विकास को गति दी जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के समान नीति–स्तरीय महत्व प्रदान किया जाए, सुलभ एवं कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराया जाए तथा तकनीकी उन्नयन एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाए। यदि वित्तीय सहायता, प्रबंधकीय प्रशिक्षण और नवाचार को संस्थागत समर्थन मिले, तो भारत में लघु उद्योग न केवल रोजगार और निवेश में वृद्धि करेंगे, बल्कि आर्थिक विकास को भी सुदृढ़ आधार प्रदान

उद्देश्य

- मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
- एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों की पहचान एवं मूल्यांकन करना।
- एमएसएमई क्षेत्र के संतुलित एवं सतत् विकास हेतु नीतिगत एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध विधि

इस शोध में मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध डिज़ाइन का उपयोग किया गया है।

समंक का स्वरूप

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों का उपयोग किया गया है–

- **प्राथमिक समंकः** चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित एमएसएमई इकाइयों के स्वामियों/प्रबंधकों से संरचित प्रश्नावली एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी संकलित की गई। इससे वास्तविक समस्याओं, वित्तीय स्थिति, तकनीकी स्तर एवं विपणन संबंधी अनुभवों का प्रत्यक्ष आकलन संभव हुआ।

- **द्वितीयक समंकः** सरकारी रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योग विभाग के प्रकाशनों, शोध पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं तथा आधिकारिक वेबसाइटों से आँकड़ों का संकलन किया गया।

नमूना चयन

अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन पद्धति का उपयोग किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) की इकाइयों को सम्मिलित किया गया, ताकि तुलनात्मक विश्लेषण संभव हो सके।

समंकों का विश्लेषण

संकलित समंकों का वर्गीकरण, सारणीकरण एवं प्रतिशत विश्लेषण किया गया।

अध्ययन की सीमा

अध्ययन मध्य प्रदेश तक सीमित है तथा उपलब्ध आँकड़ों की विश्वसनीयता पर आधारित है।

विश्लेषण

मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्यमों का क्षेत्रवार वितरण राज्य की औद्योगिक संरचना के स्वरूप को स्पष्ट करता है। विनिर्माण क्षेत्र में 40 प्रतिशत उद्यमों की भागीदारी यह संकेत देती है कि राज्य की औद्योगिक गतिविधियाँ उत्पादन–आधारित एवं मूल्य संवर्धन उन्मुख हैं। यह प्रवृत्ति रोजगार सृजन, क्षेत्रीय औद्योगिक क्लस्टर विकास तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक योगदान को सुदृढ़ करती है।

सेवा क्षेत्र में 25 प्रतिशत भागीदारी राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के क्रमिक विस्तार को रेखांकित करती है। यह वृद्धि शहरीकरण, डिजिटलीकरण तथा उद्यमिता के नए आयामों से संबद्ध मानी जा सकती है।

कृषि–आधारित उद्यमों का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य की कृषि प्रधान पृष्ठभूमि के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है, जो एग्री–प्रोसेसिंग, मूल्य श्रृंखला विकास तथा ग्रामीण औद्योगिकीकरण की संभावनाओं के अपर्याप्त दोहन की ओर संकेत करता है।

व्यापार एवं अन्य क्षेत्रों की 10–10 प्रतिशत भागीदारी औद्योगिक विविधीकरण की सीमित अवस्था को दर्शाती है। समग्रतः, यह संरचना विनिर्माण–प्रधान होते हुए भी संतुलित औद्योगिक विस्तार हेतु सेवा एवं कृषि–आधारित क्षेत्रों में लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को इंगित करती है।

मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विकास दर क्षेत्रवार भिन्न प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करती है। सर्वाधिक विकास दर सेवा क्षेत्र (10%) में दर्ज की गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीयक गतिविधियों के तीव्र विस्तार, डिजिटलीकरण, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तथा उपभोक्ता मांग में परिवर्तन का द्योतक है। यह संकेत करता है कि सेवा–आधारित उद्यम अपेक्षाकृत कम पूंजी–गहन होते हुए भी उच्च वृद्धि क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं।

विनिर्माण क्षेत्र (8%) की विकास दर संतोषजनक मानी जा सकती है, जो औद्योगिक उत्पादन, स्थानीय क्लस्टर विकास तथा आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण के सकारात्मक प्रभावों को दर्शाती है।

इसके विपरीत, कृषि–आधारित उद्योग (5%) की अपेक्षाकृत निम्न वृद्धि दर यह संकेत देती है कि कृषि–प्रसंस्करण, भंडारण एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना में संरचनात्मक बाधाएँ विद्यमान हैं।

व्यापार (6%) तथा अन्य क्षेत्र (4%) की मध्यम एवं निम्न वृद्धि दर क्रमशः बाजार प्रतिस्पर्धा, मांग की अनिश्चितता तथा सीमित नवाचार क्षमता को प्रतिबिंबित करती है।

विकास दर का पैटर्न सेवा–प्रधान संरचनात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है, जबकि कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता पर बल देता है।

तालिका 1: मध्य प्रदेश में उद्योग के अनुसार एमएसएमई का वितरण (2024–25)

	उद्योग	मध्य प्रदेश में उद्यमों का प्रतिशत (%)
1	विनिर्माण	40
2	सेवाएं	25
3	कृषि आधारित	15
4	व्यापार	10
5	अन्य	10

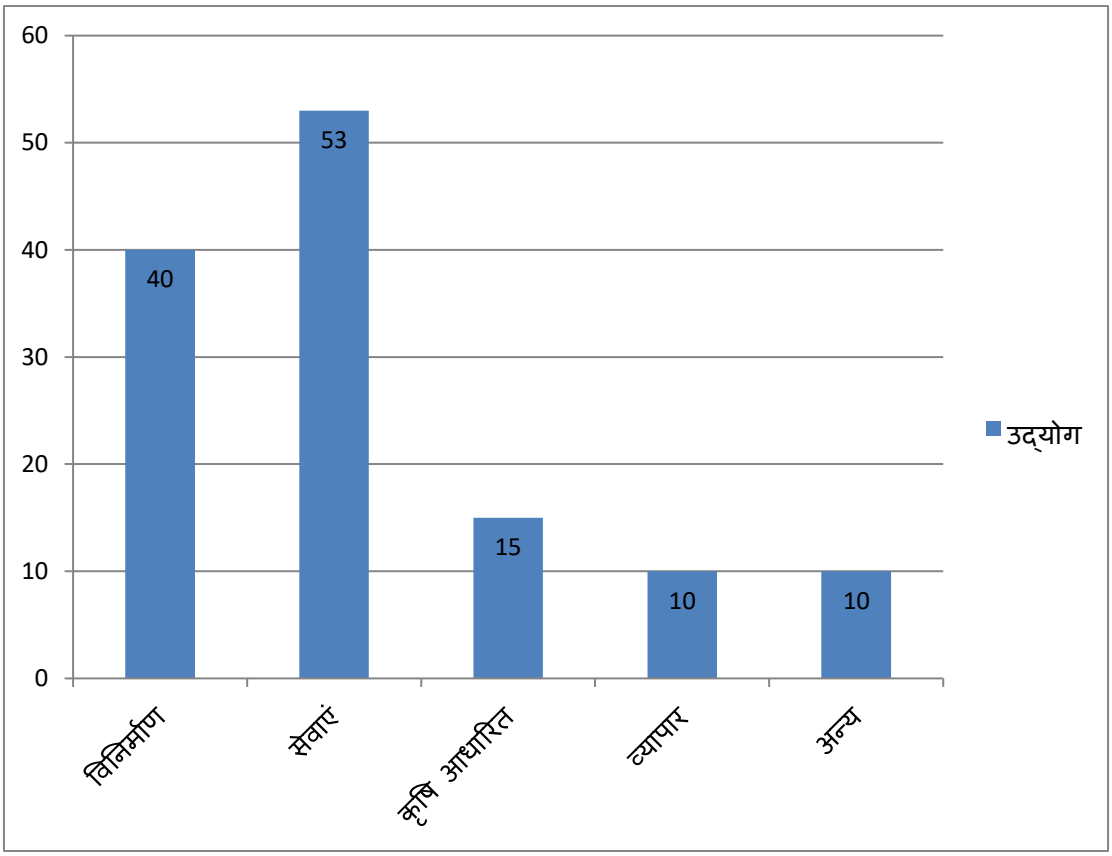

ग्राफ़ 1: मध्य प्रदेश में उद्योग के अनुसार लघु एवं मध्यम उद्यमों का वितरण (2024–25)

तालिका 2: उद्योग के अनुसार MSMEs की विकास दर (2024–2025)

	उद्योग	मध्य प्रदेश में उद्यमों का विकास दर प्रतिशत (%)
1	विनिर्माण	8
2	सेवाएं	10
3	कृषि आधारित	5
4	व्यापार	6
5	अन्य	4

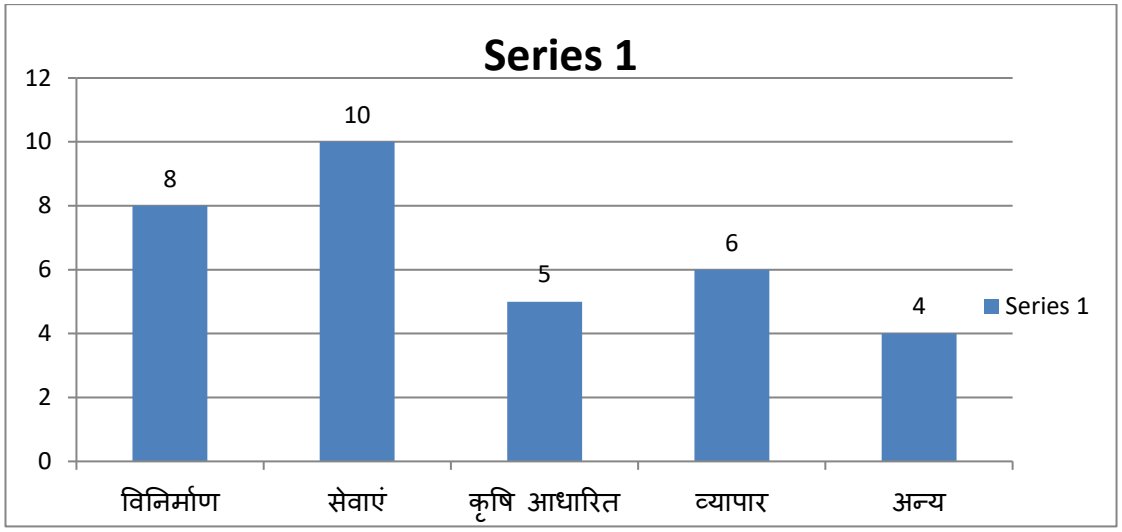

ग्राफ़ 2: उद्योग के अनुसार MSMEs की विकास दर (2024–2025)

चुनौतियाँ

- **संस्थागत वित्त तक सीमित पहुँच:** एमएसएमई इकाइयों, विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों, को बैंक ऋण प्राप्त करने में जमानत की अनिवार्यता, क्रेडिट हिस्ट्री का अभाव तथा जटिल दस्तावेजी प्रक्रियाएँ बाधक बनती हैं। इससे औपचारिक वित्तीय समावेशन सीमित रहता है।
- **उच्च ब्याज दर एवं ऋण लागत:** उपलब्ध ऋण पर ब्याज दर अपेक्षाकृत अधिक होने से पूंजी की लागत बढ़ती है, जिससे लाभांश घटता है और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।
- **कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता:** नकदी प्रवाह में असंतुलन, भुगतान में विलंब तथा कच्चे माल की अग्रिम खरीद की आवश्यकता उत्पादन चक्र को बाधित करती है।
- **अवसंरचनात्मक बाधाएँ:** गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, जल संसाधन, सड़क संपर्क, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की कमी उत्पादन लागत एवं समयबद्ध वितरण को प्रभावित करती है।
- **क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन:** औद्योगिक गतिविधियाँ मुख्यतः इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे विकसित केंद्रों तक सीमित हैं, जबकि पिछड़े जिलों में निवेश, क्लस्टर विकास एवं औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है।
- **तकनीकी उन्नयन की कमी:** पुरानी मशीनरी, निम्न स्तर का स्वचालन तथा डिजिटल तकनीकों का सीमित उपयोग उत्पादकता, गुणवत्ता एवं लागत दक्षता को प्रभावित करता है।
- **अनुसंधान एवं नवाचार का अभाव:** उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन सुधार एवं मूल्य संवर्धन के लिए नवाचार आवश्यक है, किंतु MSME क्षेत्र में R&D निवेश अत्यंत न्यून है।
- **कुशल मानव संसाधन की कमी:** तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों एवं उद्योगों के मध्य समन्वय का अभाव श्रम उत्पादकता को सीमित करता है। कुशल प्रबंधकीय क्षमता की कमी भी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
- **विपणन एवं ब्रांडिंग संबंधी सीमाएँ:** राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार तक पहुँच, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग, ब्रांड निर्माण तथा प्रभावी वितरण नेटवर्क की कमी बाजार विस्तार में बाधक है।

- **गुणवत्ता प्रमाणन एवं मानकीकरण की कठिनाइयाँः** ISO, BIS एवं निर्यात मानकों के अनुरूप प्रमाणन प्रक्रिया समयसाध्य एवं महंगी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कठिनाई उत्पन्न होती है।
- **कच्चे माल की लागत एवं आपूर्ति अस्थिरताः** कच्चे माल की कीमतों में उतार–चढ़ाव तथा समय पर उपलब्धता का अभाव उत्पादन नियोजन को प्रभावित करता है।
- **नीतिगत एवं प्रशासनिक जटिलताएँः** विभिन्न अनुमतियों, कर अनुपालन तथा नियामकीय प्रक्रियाओं की जटिलता समय एवं लागत दोनों बढ़ाती है, जिससे उद्यम विस्तार की गति धीमी पड़ती है।
- उपर्युक्त चुनौतियाँ दर्शाती हैं कि वित्तीय सुदृढ़ीकरण, अवसंरचना विकास, तकनीकी आधुनिकीकरण, कौशल संवर्धन तथा नीति–क्रियान्वयन में समन्वित सुधार के बिना मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र का संतुलित एवं सतत् विकास संभव नहीं है।

सुझाव

मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की संरचनात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित नीतिगत एवं क्रियात्मक सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं–

- **वित्तीय समावेशन का सुदृढ़ीकरणः** सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए जमानत–मुक्त ऋण योजनाओं का विस्तार, ब्याज अनुदान तथा कार्यशील पूंजी हेतु विशेष क्रेडिट लाइन की व्यवस्था की जाए।
- **कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्धताः** राज्य स्तर पर एमएसएमई विशेष वित्त पोर्टल स्थापित कर सरल एवं त्वरित ऋण स्वीकृति प्रणाली विकसित की जाए।
- **औद्योगिक अवसंरचना का विकासः** पिछड़े जिलों में औद्योगिक क्लस्टर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाएँ।
- **तकनीकी आधुनिकीकरण को प्रोत्साहनः** मशीनरी उन्नयन हेतु पूंजी अनुदान, डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना तथा Industry 4.0 आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएँ।
- **अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावाः** उद्योग–शैक्षणिक संस्थानों के मध्य सहयोग स्थापित कर R&D गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए।
- **कौशल विकास कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरणः** स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाएँ तथा अप्रेंटिसशिप को प्रोत्साहन दिया जाए।
- **विपणन सहायता एवं ब्रांड निर्माणः** राज्य स्तर पर ई–मार्केटप्लेस पोर्टल, निर्यात संवर्धन परिषदों से समन्वय तथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए अनुदान दिया जाए।
- **गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायताः** ISO, BIS तथा अन्य गुणवत्ता मानकों के प्रमाणन शुल्क पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
- **कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरणः** कच्चे माल हेतु समूह क्रय (Bulk Procurement) व्यवस्था तथा मूल्य स्थिरीकरण तंत्र विकसित किया जाए।
- **नीतिगत प्रक्रियाओं का सरलीकरणः** सिंगल–विंडो प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाकर लाइसेंसिंग एवं पंजीयन प्रक्रियाओं को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाया जाए।
- **क्षेत्रीय संतुलित विकासः** आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन पैकेज, कर रियायतें एवं निवेश सब्सिडी प्रदान की जाए।
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा दृ अवसंरचना, प्रशिक्षण एवं तकनीकी समर्थन के क्षेत्र में PPP मॉडल को अपनाकर संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

- उपरोक्त सुझावों के प्रभावी क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा रोजगार सृजन क्षमता में वृद्धि संभव है, जिससे राज्य की औद्योगिक वृद्धि एवं समग्र आर्थिक विकास को सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा।

संदर्भ गन्थ सूची

1. Singh A. K. and Shrivastav, P. K. (2022) Small-Scale Industries in India: Prospects and Challenges, YMER, Volume 21, Issuse 1,P.P. 1-9.
2. https://ymerdigital.com/uploads/YMER201309.pdf
3. Shashank, B. S. and Mayya. S. (2021) A Conceptual on Performance of Small scale industries, International Journal of Case Studies in Business, IT and Education (IJCSBE), Vol. 5, No. 2, ISSN: 2581-6942, P. P. 342-353.
4. Sarkar, A. A. (2017) Terends Opportunities and Clallnges in Small Scale industries in Assam, Volume 07, Issue ll ISSN PP,1-5.
5. Kaur, G. (2017) Ecomomic Reforms and Micro, Small and Medium Enterprises, International Journal of Research Granthalayah, Vol-5, Issue-5, ISSN- 2250-0530 :4321, P.P. 394-404.
6. vijayrani, K. R. (2011) Small - Scale indusiares in india problems and policy Initiatives, New century publications, New Dehli India.
7. Gupta, S. P. (2009) Statical Metheds, Sultan Chand and Sons Educational Publishers, New Dehli India.
8. बेसिक स्टैटिसटिक्स ऑफ एमपी भोपाल।
9. क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ मध्य प्रदेश स्टैटिसटिक्स, भोपाल – त्रैमासिक ।
10. दैनिक – भास्कर, इंदौर
11. टाइम्स ऑफ़ इंडिया
12. www.msme.nic.in
13. www.msme.gov.in
14. www.dcmsme.gov.in
15. www.mpindustry.gov.in
16. www.msme.nic.in
17. www.msme.gov.in.

❑❑❑